[Secretary]

Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 21st December, 1971, agreed without any amendment to the North-Eastern Areas (Reorganisation) Bill, 1971, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th December, 1971."

ASSENT TO BILLS

SECRETARY: I lay on the Table following three Bills passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 17th December, 1971:

(1) The Appropriation (No. 4) Bill, 1971.

(2) The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1971.

(3) The Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1971.

10.14 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

TWENTY-SECOND REPORT

SHRIMATI MUKUL BANERJI (New Delhi) : I beg to present the Twenty-second Report of the Public Accounts Committee regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Hundred and Tenth Report (Fourth Lok Sabha) relating to Customs.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Why is she presenting it?

MR. SPEAKER : She is a Member of the Committee. I think she looks quite nice while presenting.

SHRI S. M. BANERJEE : I am glad that Mrs. Banerji is doing it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Mr. Banerjee should be more chivalrous.

PAYMENT OF GRATUITY BILL

APPOINTMENT OF A MEMBER TO STATE COMMITTEE

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R.K. KHADILKAR): I move:—

"That this House do appoint Shri Hukam Chand Kachwai *vice* Shri R.R. Sharma, to the Select Committee to which the Bill to provide for a scheme for the payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, plantations, shops or other establishments and for matters connected therewith or incidental thereto, was referred by the House on the 21st December, 1971."

MR. SPEAKER : The question is:—

"That this House do appoint Shri Hukam Chand Kachwai *vice* Shri R.R. Sharma, to the Select Committee to which the Bill to provide for a scheme for the payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, plantation, shops or other establishments and for matters connected therewith or incidental thereto, was referred by the House on the 21st December, 1971."

The motion was adopted.

10.15 hrs.

DISCUSSION RE: STATEMENT ON SUGAR POLICY

MR. SPEAKER : This discussion is strictly for one hour. The moment one hour is over, this discussion will conclude. No chits will be considered. The gentlemen who stand will not be allowed. I wish to make this clear now.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Let the Members be brief.

MR. SPEAKER : We have no time we have many other things.

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दस मिनट लूगा ।

अध्यक्ष महोदय दस मिनट आप लेगे तो औरो के लिए क्या रह जायेगा ? मै समझता हू पाच मिनट प्रत्येक के लिए काफी होगा ।

श्री नरसिंह नारायण पाडेय श्रीमन पाच मिनट मे इतने बडे पालिसी मैटर के लिए क्या कहा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय पाच नहीं छ मिनट लीजिए ।

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY Mr Speaker Sir I raise a discussion under Rule 193 on the statement made by the Minister of Agriculture in the House on the 13th December, 1971 regarding Sugar Policy

Mr Speaker Sir, I want to have at least ten minutes

MR SPEAKER You may have 6 minutes

श्री नरसिंह नारायण पाडेय श्रीमन मैं निवेदन करना चाहता हू माननीय खाद्य मत्री जी से कि आप का जो यह बयान है जो आप ने 13 दिसम्बर को दिया है जिस के अनुसार 40 परसेट चीनी 14 लाख टन मे आप ने मिल मालिको के लिए फ्री छोड दिया है और 60 परसेंट चीनी आप ने कट्रोल से 2 रुपये के दर से फेयर प्राइस शाप्स से बेचने के लिए इन्तजाम की है, यह जो सरकार की चीनी की नीति है और गन्ना किसानो तथा कन्ज्यूमर्स के सबध म नीति है यह पिछले तीन/चार सालो मे कोई निश्चित नीति नही बन पा रही है जिस से तमाम कठिनाइयां उत्पन्न हैं । मत्री महोदय ने अपने बयान मे इसी सदन मे कहा है, मै उसकी चर्चा समय कम होने की वजह से नही करना चाहता लेकिन उन्होने कहा है कि गन्ने का दाम कम से कम 7 रुपये 37 पैसे इसलिए निश्चित किया जाय पर-क्विटल जिस से चीनी का भाव ऊपर न चढने पाए । लेकिन आप ने जिस समय यह हाफ हार्टेड कट्रोल किया उस के बाद आज चीनी का भाव क्या है यहां आप देखें । दिसम्बर मे चीनी 2 रुपये 37 पैसे मे रिटेल शाप पर बिकी और आज चीनी का भाव बढ कर के और ऊपर पहुच गया है । आप के इस 40 प्रतिशत रिलीज का क्या मतलब हुआ ? मैने सब आकडे निकाले है । यह जो हाफ हार्टेड कट्रोल आप ने किया उस के पहले पौने सत्ताइस लाख टन चीनी आप ने मिल मालिको को दी । इसके बाद अगर हापुड मुजफ्फरनगर और कानपुर के बाजार भाव को देखें तो साढे चार सौ रुपये की क्विटल के हिसाब से चीनी म मुनाफा उन व्यापारियो को आप ने दिया जिस का नतीजा यह हुआ कि करीब 11 करोड रुपया आप ने मिल मालिको को और डीलरो वगैरह को एकदम मुनाफा म दे दिया । 40 परसेंट जब आप ने रिलीज किया तो 6 लाख टन चीनी दिया और उससे 2 करोड रुपये के लगभग और उन को कमाये । इसका मतलब यह हुआ कि 13 करोड रुपया मिल मालिक आज आप की चीनी नीति के कारण कट्रोल के पहले और कट्रोल के बाद कमा चुके है और उन्होने जो इतनी बडी आफत देश मे आई उस मे कितना रुपया सुरक्षा फंड के लिए दिया ? आज किसानो का 13 करोड रुपया बाकी रह गया पिछले साला का । कितना रुपया अभी तक अदा किया गया ? सरकार ने मिल मालिको को चेतावनी दिया कि हम आप को जेल मे डाल देगें हम प्रान्तीय सरकार को लिख रहे है लेकिन आज भी लगभग 11 करोड रुपया, अगर मुझे ठीक से याद है किसानो के गन्ने का दाम बाकी है । आज लकडी किस भाव पर बिक रही है ? हमारे यहां लकडी साढे चार रुपये मन, यानी बारह रुपये पर क्विटल, के हिसाब से बिक रही है । आठ रुपये फी क्विटल के हिसाब से 'बगास" (खोइया) बिक रहा है । सीरा 21 50 रुपये फी क्विटल के हिसाब से बेचा जा रहा है ।

सब मुख्य मंत्रियो ने लिख कर भेजा कि गन्ने की मिनिमम प्राइस तय की जाये । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि गन्ने का भाव कम से कम 10 रुपया रखा जाये । लेकिन उस पर कनसिडरेशन नही किया गया और किसी प्रान्तीय सरकार के विचारो से लाभ नही उठाया गया । हमेशा—1930 से ले कर 1950 तक—मिल-मालिको के कहने पर कमीशन एपायंट

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

किये गये, उन के कहने पर उन की मिलों को प्रोटेक्शन दिया गया और चीनी तथा गन्ने का भाव तय किया गया।

सरकार ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि किसान को हक है कि वह गन्ने के दाम के बारे में मिल-मालिकों के साथ सौदेबाजी करे। किसान सौदेबाजी कैसे कर सकता है, जब कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों ने रिज़र्वेशन का कानून बना दिया है, जिस के तहत किसान का सारा गन्ना गिरवी रख दिया गया है? मिल-मालिकों ने गन्ने का भाव कम कर दिया है और अगर केन सोसाइटीज इस आधार पर मिलों को गन्ना नहीं देती है कि उन को गन्ने का ठीक दाम नहीं मिल रहा है, तो उन पर मुकदमे चलाये जायगे। क्या खाद्य मंत्रालय अपना बयान देते समय इन बातों को अपने सामने नहीं रखता है?

आज हिन्दुस्तान में दो करोड़ किसान परिवार गन्ने की खेती में लगे हुए हैं। अगर एक परिवार में पांच सदस्य मान लें, तो दस करोड़ लोग आज देश में गन्ने की खेती में लगे हुए हैं। यहां पर 218 शुगर फैक्टरीज हैं। हमारे किसान 'सब-ट्रापिकल" रिजन में रहते हैं। ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज के अन्तर्गत जो प्राइवेट मिलें चलती हैं उनके यहां किसानों की हालत दयनीय हो गई है।

क्या आज दुनिया में कोई ऐसा काश्तकार है जो गन्ना दे दे—अपना सामान बेचे—और उस के साल भर बाद तक उस का दाम न दिया जाये? पार्लियामेंट में 85 परसेंट सदस्य किसानों से चुन कर आते हैं। हम किसानों के नुमायदे हैं। प्रश्न यह है कि हम अपने देश के इतने बड़े उद्योग के हितों की क्या रक्षा कर रहे हैं, जिस में लगभग पंद्रह करोड़ किसान और मजदूर लगे हुए हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में 8.50 रुपये, पश्चिमी क्षेत्र में 9 रुपये और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से गन्ने के भाव तय किये हैं। चालीस पर सेंट फ्री शुगर देने के बावजूद चीनी का भाव बढ़ता चला जा रहा है। सरकार ने मिल-मालिकों को अधिक दिनों तक प्रोटेक्शन दिया। उस के बावजूद मिल-मालिक चीनी का दाम नहीं गिरा सके।

सरकार ने गन्ना-किसानों को प्रोटेक्शन नहीं दिया, जिस का नतीजा यह है कि देश में गन्ने की काश्त तीस परसेंट कम हो गई है। सरकार कहती है कि हम 1972-73 में ऐसी नीति अपनाना चाहते हैं, जिस से ज्यादा से ज्यादा चीनी पैदा हो। देश में चीनी की खपत चालीस लाख टन है। हम हर साल साढ़े चार लाख से पांच लाख टन चीनी विदेशों में भेज कर विदेशी मुद्रा अर्जन करते हैं। अगर सरकार की यही नीति रही, तो देश के इतने बड़े उद्योग की क्या स्थिति होगी, जिस में पंद्रह करोड़ किसान और मजदूर लगे हुए हैं?

मेरे क्षेत्र में चार मिलें हैं। किसान अपने खेतों को गिरवी रखते हैं और नाना प्रकार के टैक्सों की अदायगी करते हैं। आज वे रो रहे हैं। जब हम उन को गन्ने की खेती करने के लिए कहते हैं, तो वे कहते हैं कि हम गन्ने की खेती कैसे करें जब मेहनत का पैसा भी मूल्य के रूप में नहीं मिलता। इस लिए सरकार को मिल-मालिकों और पूंजीपतियों की नीति को छोड़ देना चाहिए। इस से वह देश में समाजवाद नहीं ला सकती है। क्या पंद्रह करोड़ इन्सानों को, उन के बच्चों को, भूखों मार कर, उन की जिन्दगी को दुश्वार बना कर सरकार इस देश में समाजवाद लाने की आशा रखती है? इस देश में 218 मिल-मालिकों के बल पर समाजवाद नहीं आ सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने गन्ने के भाव तय करते समय किसानों के किस नुमायदे से बात की, किस प्रान्तीय सरकार की राय ली।

इस संबंध में बहुत सी किताबें और रिपोर्टें पड़ी हुई हैं। सन 1932 में रिपोर्ट तैयार की गई। उनमें "टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट" और "शुगर एनक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट" भी है, क्यों इन आधारों पर चीनी का दाम तथा गन्ने का दाम तय नहीं किया जाता है। या तो सरकार उन किताबों को फाड़ कर फेंक दे, या वह उन के मुताबिक अपनी चीनी-नीति बनाये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य सदन में किताबें फेंक रहे हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडे टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट और शुगर एनक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को अपने गन्ने का दाम तेरह चौदह रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन मुख्य मंत्रियों ने दस रुपये का जो सुझाव दिया है, कम से कम वह तो रखना ही चाहिए। चीनी का दाम उस के मुताबिक तय किया जाना चाहिए। मिलमालिकान के होल सेलर आदि तेरह करोड़ रुपया डकार गये लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

सरकार ने फिर एक कमीशन बिठा दिया है जो मार्च में अपनी रिपोर्ट देने जा रहा है। यह कमीशन किस लिए बिठाया गया है? क्या पन्द्रह करोड़ किसानों की रक्षा के लिए जिन्होंने हम को पार्लियामेंट में भेजा है या मिल मालिकों की रक्षा के लिए यह कमीशन बिठाया जा रहा है? मंत्री महोदय साफ तौर पर अपनी चीनी नीति का ऐलान करें। वह गन्ने का भाव ग्यारह रुपये नहीं तो दस रुपये तय करने का ऐलान करें। तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिस में किसान गन्ने की खेती कर सकेंगे और चीनी का उत्पादन बढ़ सकेगा तथा किसानों मजदूरों तथा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसीलिये कांग्रेस ने बम्बई में मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पास किया जिससे किसान मजदूरों तथा उपभोक्ताओं को उचित हक मिल सके तथा उत्पादन तथा वितरण पर सरकारी नियंत्रण रहे।

अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने लाइब्रेरी की किताब फाड़ी या अपनी?

SHRI D K PANDA (Bhanjanagar) It is an expression of the genuine feelings

अध्यक्ष महोदय लाइब्रेरी बुक्स का भी प्रिविलेज आ सकता है।

That is too bad

श्री नरसिंह नारायण पांडे अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो मैं ये किताबें आप के पास भेज सकता हूं।

MR SPEAKER Are they the Library books or the hon Member's own?

SHRI NARSINGH NARAIN PANDE They are from the Library

MR SPEAKER We shall have to charge if the binding is damaged

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) अध्यक्ष महोदय मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गन्ने के कम से कम दाम किस आधार पर तय किए गये हैं। क्या इस सम्बन्ध में गन्ने का कास्ट आफ प्रोडक्शन निकाला गया है या नहीं? क्या इस बारे में लोक सभा के किसी ऐसे सदस्य को कान्फिडेंस में लिया गया है या नहीं जो किसानों का रिप्रेजेन्टेटिव हो और जो किसानों की हालत को जानता हो? सरकार की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया है उस में कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिकवरी 9 परसेंट से कम है और वहां पर 9 रुपये दिये जा रहे हैं। बिहार में रिकवरी साढ़े नौ परसेंट है लेकिन वहां पर गेट पर साढ़े आठ रुपये और आउट स्टेशन पर आठ रुपये दिये जा रहे हैं। मेरे जिले में जहां बिहार का आधा शुगरकेन पैदा होता है रिकवरी साढ़े नौ परसेंट है लेकिन वहां पर आठ और साढ़े आठ रुपये दिये जा रहे हैं।

संविधान में सोशल जस्टिस की बात कही गई है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कैसा सोशल जस्टिस है कि इस तरह भिन्न भिन्न कीमतें तय की जा रही हैं। सरकार को कीमत तय करने की स्टैचुटरी राइट है। तब फिर वह मिल मालिकों के दरवाजे पर क्यों जाती है? सरकार मिल मालिकों और किसानों के प्रतिनिधियों को बुला कर दाम तय करे। यह पार्लियामेंट एक सोविरेन बाडी है। जहां तक प्राईस कमीशन का सम्बन्ध है, वह पूरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि वे लोग शहर के रहने वाले हैं और उन को गांवों में कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है। इसलिए वे शहर वालों और बड़े बड़े धनिकों के हित में कीमत तय कर देते हैं।

एक दिक्कत हमारे यहां अध्यक्ष की रिजर्वेशन की है। हम अपना गन्ना दूसरी जगह नहीं दे सकते। अगर दूसरी जगह दें तो हमारे ऊपर ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत फौजदारी का मुकदमा चलाया जायगा। इसलिये हम को लाचारी है। मेरे यहां स्थिति भिन्न प्रकार की है, बिहार में गुड़ या खांडसारी नहीं बनती

[श्री विभूति मिश्र]

है, हम को लाचार हो कर गन्ना शुगर फैक्ट्रियों को देना पड़ता है। मंत्री जी कहते हैं कि अगले साल 33-34 लाख टन चीनी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार डिस्कशन में कहा था कि आप का यह अन्दाजा बिल्कुल गलत है। 40 फीसदी गन्ना तो हमारे जिले में डैमेज हो गया है। आप के टारगेट तो वही हैं जो सरकारी नौकर आप को दे देते हैं। वे शहरों में बैठ कर अपनी रिपोर्ट बना देते हैं लेकिन सही जानकारी उन के पास नहीं होती है, इसलिये आप के ये सब आंकड़े गलत हैं।

अध्यक्ष जी, हमारी प्राइम मिनिस्टर भी हमारे हक में हैं। मैं जानता हूं हमारे मंत्री जी कहेंगे कि कैबिनेट में इस के बारे में फैसला हो गया है, लेकिन मैं उन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस मामले को एक बार फिर कैबिनेट के सामने ले जायं। मैं जानता हूं हमारी प्राइम मिनिस्टर की किसानों के साथ हमदर्दी है, जिस तरह से पहले इस के बारे में कैबिनेट में लड़ाई की, इस को भी फिर से वहां ले जाकर कीमत के बारे में फैसला करावें।

मेरे यहां बाढ़ से बरबादी हुई है। गेहूं की फसल बरबाद हो गई है। गन्ने की फसल एक मनी क्राप है, लेकिन इस में भी बीमारी लग गई, जिस की वजह से गन्ना कम हुआ। ऐसी हालत में किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। आप ने कहा कि हम कीमत नहीं बढ़ायेंगे, लेकिन 50 करोड़ रुपया सरकार ने एम्पलाइज की तनख्वाह के रूप में बढ़ा दिया। किसान की अपनी उपज का दाम तो कम देना चाहते है, लेकिन किसान को अपनी जरूरियातों के लिये जो खरीदना पड़ता है उस के दाम उसे ज्यादा देने पड़ते हैं। कपड़ा, नमक सब कुछ महंगा है। नमक हमारे यहां 27 रुपये बोरी बिक रहा है। मिट्टी के तेल की बोतल 1 रु० से 1 रु० 25 पैसे में मिल रही है। किसान की चीज का कोई मोल नहीं है, लेकिन फैक्ट्रियों की जो चीज किसान को खरीदनी पड़ती है सब के दाम ज्यादा हो गये हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर फिर से विचार करें और 10 रु० क्विंटल की जो मांग है, उस को अवश्य दें। यह कहा जाता है कि हम कीमतों को नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन कीमत बढ़ने के नाम पर 50 करोड़ रुपया आपने सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाइज को दे दिया, किसान के लिये आप ने क्या किया ?

जब हम किसान का एक अलग संगठन बनाना चाहते हैं तो हमारी पार्टी के नेता कहते हैं कि किसानों का अलग संगठन बनाओगे तो कांग्रेस कहां रहेगी। लेबर का संगठन बने तो कांग्रेस नहीं घबराती किसानों का संगठन बने तो हमारी पार्टी वाले घबरा जाते हैं, लेकिन किसानों के लाभ के लिये, उस की आजीविका के लिये बात भी नहीं करना चाहते हैं। पूंजीपतियों के बारे में बात होती है, लेबर यूनियन की बात होती है, सरकारी एम्पलाइज की बात होती है, जब ये सारी बातें होती हैं तो किसानों की बात क्यों नहीं होती। यह सरकार तो सब की सरकार है इसे सब के लिये समान रूप से सोचना चाहिये।

इस लिये मैं मंत्री महोदय से फिर अनुरोध करता हूं कि इस को फिर से कैबिनेट में ले जायें और हम लोगों की बात, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, वहां पर रखें। यदि हो सके तो हम को अपनी बात वहां कहने दी जाय, उस के बाद जो फैसला होगा उस को मानेंगे, लेकिन एक बार कैबिनेट में जरूर ले जायें। प्रधान मंत्री जी इस के लिये राजी हैं कि इस के ऊपर विचार किया जाय और किसानों के हक में फैसला किया जाए ताकि किसानों को राहत मिले।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, मैं पाण्डे जी को बधाई देता हूं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। यह कुछ सत्य है कि सरकार की चीनी के सम्बन्ध में कोई सुविचारित और सुनिश्चित नीति नहीं है। नीति ऐसी होनी चाहिये जो गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों का संरक्षण करे। स्पष्ट है कि इस नीति के अन्तर्गत मिलों को भी उचित मुनाफे की गुंजाइश होगी, लेकिन अभी तक का अनुभव यह बताता है कि सरकार की नीति ने न तो गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा की है और न उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देने से बचाया है। आज बाजार में चीनी दो रुपये 30 पैसे से 2 रुपये 35 पैसे किलो तक बिक रही है....

(व्यवधान)...मैं चीनी खरीदता हूं। चीनी खाते तो आप भी होंगे, लेकिन खरीदते नहीं होंगे। आप स्वीकार करेंगे कि या तो चीनी का भाव घटे और उपभोक्ताओं को राहत मिले और अगर सरकार इस में असमर्थ है तो फिर गन्ना उत्पादकों को उस के मुनाफे का पूरा पैसा दिलाने का सरकार को प्रबन्ध करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति ऐसी है कि कभी तो चीनी की पैदावार बढ़ जाती है, लेकिन पैदावार बढ़ने के बाद भी गन्ने के दाम नहीं बढ़ते और गन्ना पैदा करने वाले किसान को उस का उचित पैसा नहीं मिलता। मुझे डर है कि गन्ने के दाम नहीं बढ़ाये गये और किसान को गन्ना पैदा करने के लिये प्रोत्साहित नहीं किया गया तो देश में चीनी का अकाल पड़ जायगा। यह अकाल अगले साल प्रारम्भ हो जायगा और अगले साल के बाद के साल में स्थिति और ज्यादा गम्भीर हो जायगी। यह भी आवश्यक है कि सरकार चीनी, गुड़ और खाण्डसारी के सम्बन्ध में एक समन्वित नीति बनाये। अभी तक इस तरह की कोई नीति नहीं बनाई गई है। इस में सन्देह नहीं कि कुछ कमेटियां बनी हैं, कमीशन बने हैं, उन के प्रतिवेदन आये हैं, लेकिन उन पर आचरण नहीं किया जाता। मैं समझने में असमर्थ हूं कि किसी राज्य में गन्ने के दाम बढ़ा दिये गये हैं, किसी में नहीं बढ़ाये गये है। उत्तर प्रदेश में गन्ने के दाम न बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार---इन की सारी अर्थव्यवस्था चीनी उद्योग पर निर्भर करती है। किसानों की हालत ऐसी है कि गन्ना टिकता है बाढ़ पर और बाढ़ प्रतिवर्ष इन क्षेत्रों में आती है, इस लिये किसान गन्ना पैदा करना अधिक पसन्द करता है। लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि किसान गन्ने के लिये मिल-मालिकों से सौदे-बाजी करे। मजदूरों के बारे में यह बात सही हो सकती है, वे सौदेबाजी कर सकते हैं, लेकिन वह इस स्थिति में नहीं है क्योंकि उस के सामने एक कठिनाई है कि वह उस गन्ने को खेत में खड़ा नहीं रख सकता है। मिल-मजदूर हड़ताल कर सकते हैं, पेट पर पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन गन्ना पैदा करनेवाले किसान के लिये ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि उस का गन्ना सूख जायगा और सूख जाने से उस को और कम कीमत मिलेगी, उस का जीवन बरबाद हो जायेगा। यह मामला मिल-मालिकों और गन्ना उत्पादकों की सौदे-बाजी पर नहीं छोड़ना चाहिये।

मैं समझता हूं कि सदन की भावनाओं को कृषि मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे। आज की स्थिति में गन्ने का दाम कम से कम 10 रु० प्रति क्विंटल होना चाहिये। आप मिलों को निर्देश दें कि वे गन्ने का भाव बढ़ाये और शहरों में रहनेवालों के लिये चीनी उचित मूल्य पर मुहिया करने का प्रबन्ध करें। मैं चाहता हूं कि दोनों पहलुओं पर विचार कर के निश्चय किया जाय। चीनी की आवश्यकता सभी को है, चाहे नगर में हो या गांव में हो, उसको उचित मूल्य पर चीनी मिले और गन्ना पैदा करनेवाले किसानों को इतना मूल्य दिया जाय जिससे वे गन्ना पैदा करने के लिये प्रोत्साहित हो सकें।

SHRI PILOO MODY (Godhra): I have been studying the sugar problem for some time and I have come to the conclusion that the Government has no policy on sugar at all, not even a short term policy much less a long-term policy and they move from moment to moment and from day-to-day to suit their petty political purposes. This is a very serious charge that I am making against the Government.

The production of sugar has fluctuated up and down, all the way from 45 lakh tonnes to something like 22 lakh tonnes, and next year we are expecting not more than 33 lakh tonnes, which is a good 11 lakh tonnes short of our requirements if we are to maintain the same level of exports. I cannot understand how, faced with these facts, Government cannot come up with a policy which will solve these problems on an emergency footing. I cannot understand how the Government can expect a shortfall of 11 lakh tonnes this year and still continue with the basic price of sugarcane as it has been for the last six or seven years.

If you were to study the figures of production and the base price of sugarcane you will see that every time the price has been

[Shri Piloo Mody]

increased, over a period time production has gone up The production had gone up al the way up to 45 lakh tonnes two years ago, and has started falling again But the Government has not woken up to that fact they say that even though we fix base price of sugarcane, the sugarcane grower in fact gets more than this base price This is their only argument This is not an argument which is going to increase your production You have to bring about a reality in the price that you fix

They have fixed certain criteria, about five or six, for arriving at the base price of sugar If you apply those criteria, under no circumstances can you arrive at the same figure year after year Therefore, I strongly doubt the *bona fides* of those who fix the sugarcane price I do not think it has any relevance either to the criteria framed by themselves or to the realities of the situation Production costs are going up, the cost of living is going up, everything is going up, but the price of sugarcane must remain the same I cannot be a party to such logic

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) अध्यक्ष महोदय, यह जो चीनी का सवाल है वह काफी देर के बाद बहस मे आया है। यह सवाल बहुत जरूरी था। इससे पहले भी इसका नोटिस दिया गया था लेकिन उस वक्त वह नही आ पाया। यह एक ऐसी चीज है जिस पर बार बार आदरणीय मेम्बरो की तरफ से कहा गया है कि चीनी के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है और यह बात बिल्कुल सत्य है। इसमें न तो किसानो के हित को देखा जाता है और न उपभोक्ता के हित को देखा जाता है। एक बहुत बड़ी चीज जो देखने मे आ रही है वह यह कि किसान को बहुत ज्यादा अमीर मान लिया गया है। हिन्दुस्तान के किसानो में 70-80 फीसदी तक छोटे किसान है। उसके बाद दस पांच फीसदी और मिलाये तो मार्जिनल किसान है। लेकिन सभी कामेंमे को एक तरफ से अमीर मान लिया गया है और उसकी फसलों की बिक्री के बारे में सरकार ने कोई नीति निर्धारित नही की है। किसान हमेशा महगा पैदा करता है और सस्ता बेचता है। वह जब कज्यूमर बन जाता है तो उसको बाजार मे जरूरत की सभी चीजे ऊचे मूल्य पर मिलती है क्योंकि उन चीजो का प्राईस इन्डेक्स कभी भी नीचे नही आता है। वह हमेशा उपभोक्ता बनकर भी घाटे मे रहता है और प्रोड्यूसर बनकर भी घाटे मे रहता है। किसान की उपज बढ़ाने के लिये जो मशीन है या तेल है, सभी चीजो की कीमत ज्यादा होती है। और उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि उन चीजो की क्वालिटी भी खराब होती है। जितनी भी मशीनें किसानो को सप्लाई की जाती हैं ऐसी बोगस कम्पनिया मौजूद हैं जो बाहर से मशीनो को धक्का दे देती है और उसके बाद वह चलती है या नही चलती है। उसको जो पेट्रोल या डीजल मिलता है वह भी एक मिलावट की चीज होती है जिससे उसकी मशीनों की कीमतें गिर जाती है। किसानो की मशीनो को ठीक रखने के लिए सरकार की कोई नीति नही है। सरकार कोई भी ऐसी नीति नही अपनाती जिससे कि एक कीमत पर उसको चीज मिल सके और फिर किसान को भरोसा हो सके कि अगली बार हमे यह देना होगा।

मेम्बर्स को पता होगा कि आज भी किसान जेलो मे बन्द होते हैं। कोई भी सख्श जेल मे उस समय जाता है जबकि उसके पास पैसा नही होता है। मैं सहारनपुर जिले की बात कह सकता हू, आप पिछले दो तीन सालो की बात ले लीजिए, तहसील की हवालात मे किसान आज भी सरकार की देनदारी अदा न करने पर पेमेन्ट न करने पर बन्द हैं। लेकिन सरकार के दिमाग मे एक ही चीज बैठी हुई है कि किसान के द्वारा पैदा की गई चीजों को सस्ता रखो तो देश मे महगाई नही बढ़ेगी जबकि अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत है। किसान की चीज हमेशा सस्ती रही है, उसका भाव हमेशा गिराया गया है और महगाई का वही शिकार होता है क्योंकि पहले बाजार की दूसरी चीजे ही महगी होती है। जब भी महगाई का दौर आता है तो पहले दो तीन साल तक किसान को उपभोक्ता के रूप में महंगी चीजें खरीदनी पड़ती है। लेकिन जब कभी किसान की चीज महगी होती है तो सरकार की निगाह उसकी तरफ जाती है और वह चाहती है कि किसान की चीज को सस्ता कर दिया जाये। सस्ती

की शुरूआत किसान की चीज से ही होती है लेकिन उसके बाद भी बाजार की दूसरी चीजें महंगी ही होती जाती हैं ।

जहां तक चीनी का मामला है, क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि कीमत तय करने का आधार क्या है ? सात रुपये 37 पैसे प्रति क्विंटल गन्ने का दाम तय करने का आधार क्या है, यह सवाल एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी में भी पूछा गया था कि किसानों की जो उपज है उसको बेचने के लिए सरकार ने क्या आधार तय किया है, क्या आंकड़े तय किए हैं लेकिन इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब वहां नहीं दिया गया । आज भी हम पुनः मन्त्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वह कौन सा आधार है जिस पर सात रुपये 37 पैसे प्रति क्विंटल का भाव रखा जाता है ? कौन से वे आंकड़े हैं जिनके अनुसार यह बताया जा सकता है कि चीनी की जो कीमत सरकार ने तय की है वह कीमत कायम रहेगी ? आप दो रुपये की बात कर रहे हैं लेकिन अभी यहां पर माननीय सदस्यों ने बताया है कि दो रुपये 37 पैसे में चीनी बिक रही है । इस तरह से आप उपभोक्ता को बचा नहीं पाते और किसानों को उनका उचित दाम दिला नहीं पाते । अब तो एक और भयानक चीज होने वाली है जो कि हमारे किसानों, उपभोक्ताओं और सारे नेशन के लिए खतरनाक होगी । जैसा कि अभी हमारे वाजपेयी जी ने कहा और हमारे पीलू मोदी जी ने कहा कि देश में चीनी की पैदावार घटती जा रही है । हमने भी इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन किया, चिट्ठी लिखी, डेपुटेशन लेकर प्रधान मन्त्री जी के पास गए और उनसे यह कहा कि यह गन्ना बोने का समय है, किसानों को प्रोत्साहित करने का यही मौका है । अगर किसानों को इस समय भी गन्ने का पूरा पैसा नहीं दिया गया तो आप जानते हैं किसान आज इन्डस्ट्री के तौर पर खेती करता है, अब वह रूढ़िवादी किसान नहीं रह गया है कि चाहे जो हो वह तो गन्ना बोयेगा ही बल्कि अब वह गन्ने का मुकाबला धान से, मैंदी से करेगा, वह गन्ने का मुकाबला गेहूं से करेगा, दूसरी कैश क्राप्स से करेगा और अगर उसको कैश क्राप्स के मुकाबले पर गन्ने में कम पैसा मिलेगा तो वह लाजमी तौर पर गन्ना नहीं बोयेगा ।

इसके अलावा गन्ने पर जो किसान का बकाया पड़ा है उसकी हालत इस वर्ष बिगड़ी हुई है कि आज किसान पर्चियां रखकर कपड़ा खरीद रहा है और दूसरे सामान खरीद रहा है । आपके यकीन के लिए मैं अपने जिले सहारनपुर के सरसावा बाजार की बात करता हूं । वहां पर एक कोआपरेटिव मिल भी है और एक छोटा सा बाजार भी है । उस बाजार में जो दुकानदार हैं वे किसानों की पर्चियां रखकर सामान देते हैं । जिस दिन किसानों का पेमेन्ट होता है तो सोसायटी के दफ्तर में वही दुकानदार किसानों की पर्चियों का पेमेन्ट कराते हैं । आज ऐसी स्थिति आ गई है कि किसान अब गन्ना बोने के लिए तैयार नहीं होगा । इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि गन्ना बोने का टाइम आ रहा है, अभी जनवरी और फरवरी में गन्ना बोया जायेगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कम से कम अब फौरन गन्ने का भाव दस रुपये प्रति क्विंटल कर दीजिए । अब तो मिल मालिक भी इस बात को मान रहे हैं । पहले मिल मालिक इसका विरोध किया करते थे लेकिन आज वे भी मान रहे हैं कि इतना दाम देना चाहिए । दूसरी प्रदेशीय सरकारें भी मान रही हैं, केन फेडरेशन भी इसको मान रहा है, एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी भी मान रही है और इस सारे हाउस का यह सेन्स भी है फिर बात ही क्या रह जाती है । वरना जैसा मैंने पहले बताया अगले सालों में गन्ने की भारी कमी हो जाने की संभावना है और फिर चीनी का भाव 5 रु० या 6 रु० किलो तक जा सकता है । यदि इस देश के कंज्यूमर्स को बचाना है तो भी जरूरी है कि प्रोड्यूसर्स को 10 रु० क्विंटल का भाव दिया जाये । मैं आशा करता हूं सरकार फौरन इस मामले पर ध्यान देगी ।

*SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia) : Mr. Speaker, Sir, many discussions have taken place in this House on the Government's sugar policy but every time we have found that Government have been pursuing a policy to protect the sugar mill-owners and the interest of the sugarcane cultivators and consumers have been ignored. Many agitations have taken place to raise the price of sugarcane but the Government have not yet fixed the minimum price

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri S. P. Bhattacharyya]

that will be given to the cultivators nor any firm arrangement has been made to pay them in cash

Sir, the House has in the past discussed the question of arrears that fall due to the sugarcane cultivators The sugarcane cultivators are compelled to sell sugarcane to the millowners even on deferred payment basis because they cannot keep the crop standing in the field but they do not get their payment and it runs into arrears The hon Members from U P and Bihar have already stated about the difficulties that are being experienced by the sugarcane cultivators in their States Not that the Government are unaware of these things but they have not done anything to ameliorate the difficulties of the cultivators The Government have always been saying that they have adopted a good sugar policy but the policy, we find, does not take into account the difficulties of the cultivators and unless the difficulties of the cultivators are removed the policy cannot be termed as a 'good policy' as is being claimed by the Govt Even in today's statement no guarantee has been given by Government about the payment to be made to the sugarcane growers and about cash payment

Sir, today 'Bangla Desh' is a free country They will be requiring sugar from us and this will raise demand for sugar. But unless we are able to fix the consumers' price for the sale of sugar and give a guarantee about the stability of the price, be it at Rs. 2 or Rs. 2 10 per Kg., the profiteers will take advantage of the situation and make hay. In Delhi and in West Bengal sugar is being sold at Rs. 2.50 per Kg. When this sugar will be exported to Bangla Desh, it will be sold for Rs. 3 per Kg. Thus the Government is only making exploitation by the millowners more smooth by their own action. As a result of the Government's policy the sugarcane cultivators and the consumers are being harassed alike and in this matter, as I have already stated, the Government are indirectly helping the sugar millowners to exploit these two classes of people. Until and unless this exploitation is stopped, we can never improve the sugar policy On the other hand, if the Government are able to correct their present policy, then with the growth in demand for sugar, which is increasing and will further increase in future, more progress can be achieved in this field

Sir, the Ahmedpur (Birbhum) Sugar Mill was closed down in West Bengal The millowner did not pay the sugarcane suppliers which amounted to Rs 1 lakh The machines were either sold cheap or they were got lotted Sir, if only the Government adopt a good policy, the production of sugar can be raised, the production of sugarcane can be raised, the consumers can get sugar at a reasonable price and the lot of the cultivators can also be improved But instead of doing this if the Government continues to issue only statements and allow the millowners to exploit the consumers and the cultivators, no good will come out of it Therefore, the policy has to be corrected and Government must adopt a firm policy which will guarantee price for the canegrower on the one hand and also a fixed sale price of sugar for the consumer on the other The sale price of sugar should not be more than Rs 2 and if any one charges more than that the traders' property should be confiscated and he should be punished. The money thus derived can be donated to the Defence Fund Let Government adopt a firm policy to ensure that the consumers get sugar at a reasonable and fixed price and also the cultivators their legitimate due. With these demands, Sir, I conclude my speech.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, we have heard a rumour that the Constitution Amendment Bill is not coming up for consideration today.

MR. SPEAKER : It is not a rumour; you know it well.

SHRI S. M. BANERJEE : But it has not yet been announced officially. If that is correct, we must congratulate the Prime Minister for her wisdom.

MR. SPEAKER : She has always wisdom.

SHRI S. M. BANERJEE : Now that we will have some surplus time, I suggest there should be a discussion on the international situation. Since Shri Swaran Singh is not here, we are not going to discuss the United Nations. But we want to discuss two other issues.

MR. SPEAKER : He has a knack of raising such issues.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, you will not hear my voice for two months from now. One is about the release of Sheikh Mujibur Rehman...

MR. SPEAKER : You know the knack of getting time for what you want and I am always alert about it.

SHRI S. M. BANERJEE : And the second point is that Bangla Desh leaders have demanded an international tribunal to try those military officers who butchered people in Bangla Desh even after surrender. Before surrender also, they raped our sisters and mothers. So, naturally, there should be some international tribunal to try them.

These are the two important issues. Then, there is the question about the conduct of several countries during the war as to who supported us and who opposed us, as to who helped us and who did not help us. Kindly allow 2 hours discussion on it. I hope, I am supported by all the leaders of various parties.

MR. SPEAKER : I am not in a position to allow what is not there on the agenda today. Moreover, the Government made its position very clear the other day. The Minister keeps making it clear every day. There are certain reasons; they do not want to come forward with the discussion unless the Foreign Minister returns. Unfortunately, he has been very busy, and usefully busy, there. (*Interruption*)

SHRI S. M. BANERJEE : Let them make a statement about Sheikh Mujibur Rehman.

MR. SPEAKER : It is for them.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) : The Prime Minister should make a statement at least about Sheikh Mujibur Rehman. So many things are coming in the papers. Are we to believe them? (*Interruptions*)

SHRI S. M. BANERJEE : We want a statement from the Government about it. Today is the last day of the session. Let a statement be made about it. (*Interruption*)

MR. SPEAKER : The Foreign Minister is not here...

SHRI S. M. BANERJEE : Let a statement be made about Sheikh Mujibur Rehman. The Foreign Minister has nothing to do with it. That is not in the United Nations.

MR. SPEAKER : That is all right. You have said what you wanted to say.

DR. RANEN SEN (Barasat) : There is another important point which was raised by Shri S. M. Banerjee...

MR. SPEAKER : I am not allowing you. One of your Members has already spoken.

DR. RANEN SEN : The point is...

MR. SPEAKER : Without my permission, nothing will be recorded. I have not permitted it.

DR. RANEN SEN : **

MR. SPEAKER : You know my position. What has the Speaker to do? Let anything come; let them be ready. I will sit even for the night. When you know the whole position, why do you go on like that ?

SHRI S. M. BANERJEE : Let them make a statement about Sheikh Mujibur Rehman at least.

MR. SPEAKER : I understand the Constitution (Twenty-eighth Amendment) Bill is not coming.

AN HON. MEMBER : Let them withdraw it. (*Interruption*)

The rule is that under Rule 194(2) the maximum time would be one hour. I think, if the Constitution Amendment Bill is not coming, we can relax the rule with your permission.

11 hours

SOME HON. MEMBERS : Yes, yes.

MR. SPEAKER : I think I need not have asked you. Even without my permission, you would have continued. But this is the formality. Half an hour for this and then the other matter about the killing of Santhals we can have a little time more and after that I will say you good-bye.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : There is one matter connected with this Constitution Amendment Bill which has been withdrawn. In the papers it has come out that there will be elections all over India excepting in the three States of Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. So I want to ask Government whether it is the decision of the Government.

MR. SPEAKER : You can ask it at some other time. Unless we know something about...

**Not recorded.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : They must come forward with a statement. We are not going to meet tomorrow. Then neither you nor we will be here... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : You are a wise man. Will you please hsten ?

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : But, Sir Mr. Munsi is going around West Bengal and spreading all sorts of rumours (*Interruptions*)

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta South) : I will teach you another political lesson.....(*Interruptions*) I carry no weapon. I am wielding only a political weapon.

MR. SPEAKER : You want to quarrel even without any occasion?

PROF S. L. SAKSENA (Maharajganj) : Sir, the conditions this year are not different from the conditions that prevailed in the country in 1968. 40% free-sale was allowed and 60% was controlled sugar that year as well. At that time the sugarcane prices were Rs. 18 to Rs. 13 per quintal. Those were the prices. But even though we have now fixed 40% free sale, still the price of sugar cane is Rs. 8.50 in East U.P. while it was Rs. 12.75 at that time. So, I want to say that this is very wrong. You say that we can strike a bargain. If you want us to bargain, we can do it. But we do not want to do it. You must remember that gur is selling at a price of Rs. 100 per quintal and the canegrower gets Rs. 12 at home itself while after spending the whole night in the winter, at factory gate he gets only Rs. 8.50. I, therefore, say that the Government must fix the price for sugarcane at least at Rs. 12 per quintal. In fact, the sugarcane price paid to the grower should be Rs. 15 or Rs.16 because that is the price at which sugarcane was sold in 1968 when 40% sugar was given for free sale. It is

in Government's own interest that if they want more sugar, they must raise the price of sugarcane Otherwise, cane will go to gur and khandsari units and not to the sugar mills The sowings of sugarcane in January and February will also be low if price of sugarcane is not raised This is one aspect which I want to point out If we want to avoid sugar famine this year and next year we must increase the price of sugarcane to at least Rs 12 per quintal This is very essential There should be a proper policy on sugar There is no sense in saying that sugar price will not be raised The price of every other thing has been raised I am sure Government will take into consideration all these aspects Government are always saying that the price of sugar should not be allowed to rise very high It is only possible when the price of sugarcane is increased I can tell you that the price of sugar will be Rs 3 to Rs 4 per kilo in March when Parliament meets again You can't stop it But the grower will not get his due if you don't raise the cane price

SHRI K NARAYANA RAO (Bobbili) It is clear from various reports that the sugar industry is cyclical in character The Government have not correctly regulated the cane price to be payable to the cane growers Whenever sugar price increases there will be a tendency for canegrowers to increase the production But once there is unexpected growth, then the prices will fall There will be competition from the gur industry and from the khandsari industry Therefore, in all this situation, the only person who is affected is the cane grower He is not compensated. He is not getting benefit When there is shortfall he is compelled to give sugarcane to the sugar factories. When there is surplus he has to face lot of difficulties and hardships in supplying the sugarcane to the sugar factories.

Molasses is one of the important ingredients that comes from sugarcane Under the Essential Commodities Act the price is fixed at a very low price The fixed price of molasses is Rs 6 and odd per quintal whereas its real value in the market is about Rs 100 I want the Minister to consider this aspect

There is one more point that is to be highlighted The Government fixes the minimum price, but unfortunately, it is understood by the sugar industry as the maximum price The minimum price is fixed on the basis of the minimum sucrose content in the sugarcane This varies from State to State Such being the case there is every reason that the minimum price of sugarcane should be regulated in consonance with the varying content of sucrose in different States This is an aspect which the hon Minister should consider

SHRI D K PANDA (Bhanjanagar) At the outset I thank you, Mr Speaker for having allowed discussion on this subject because there is some realisation that there is a real crisis in the sugar industry among the canegrowers and also among consumers

The Government has been following a policy which has been favouring only millowners Mr Pandey has stated the facts All the facts go to show that the policy which has been followed has been helping only the sugar mill owners like Mody and Birla to harvest more and more profits

I will give one or two examples to show how the Government has bowed down its head, how the Agriculture Ministry has bowed down its head before the sugar millowners They demanded decontrol of sugar, and the Government allowed it They effected it. What has

[SHRI D. K. Panda]

happened ? Before decontrol, the price of sugar per kilogramme was Rs. 1.63, and after decontrol, what is the price ? It is already admitted by everybody, and the Government has also fixed it at Rs. 2.10, though actually the price which is obtaining in the market is from Rs. 2.25 to Rs. 2.40. Who has harvested the maximum profit because of the price rise in sugar ? It is the same Birlas, Modies and the big capitalists in the sugar industry.

Further, the Government has given another concession in the form of rebate on sugar production; between 1st October, 1971 and 30th November, 1971, if any, sugar has been produced, then, in excess of 80 per cent of the sugar production, the factories were allowed a rebate of Rs. 17 per quintal. On account of this also, it is the same sugar millowners who have again harvested a windfall.

Thirdly, in reply to a question that was tabled, the Minister, Shri Sher Singh, made an observation from which also it is very clear that so many other concessions have been given to the very same sugar millowners, because they have the sugar millowners' association which is a very old one, and they are quite properly organised; they are strong enough to exert pressure on the Government. So, the Government has been consulting them only, and have been again giving one concession after another. They have banned even the crushing by power-crushers in the khandsari units. All this was only meant to help the sugar millowners.

The arrears of cane prices are there with the same sugar millowners. In Uttar Pradesh alone, there are Rs. 13 crores and in Bihar, there are still Rs. 2 crores pending. All these years, it is the very millowners who were taking away the interest and were enjoying the heavy interest on that very money which could have been given to the canegrowers and the canegrowers could have definitely produced more sugarcane if that money had been given to them. After having been tired of waiting and waiting, the growers have now diverted to other crops.

Now the crisis is that there is going to be a shortage of sugar production. Next year, we shall be facing a crisis in sugar. From that point of view, may I ask why the Government are consulting only the sugar millowners ? As per the statement, it is very, very clear. I would say that this statement has designedly demonstrated the policy of this Government,—how they are favouring these very millowners. Why they are wedded to such capitalist interest, I do not understand. From this statement, it is also shown that the Government have consulted only the joint stock companies and the cooperative sectors; not the canegrowers' association. There is the All India Canegrowers' Association in India, of which Mr. Genda Singh, who is now ill, is the President.

Mr. Pandey and 75 other Members of this Parliament also made a representation, and they submitted a memorandum to the Prime Minister and we met the Minister of Agriculture several times. There was a debate for four hours, and the Speaker was kind enough to extend it to another two hours in the last session. In spite of all these things, the Government are going on paying careful attention to the demands of the sugar millowners and are contributing in that way to the illegal amassing of wealth of these sugar millowners, on the one hand. On the other hand, they are violating the statutory provisions under the Cane Control Order in respect of the fixation of cane-price. It is not the canegrowers who are to beg here, or on behalf of the canegrowers we are not going to beg the Min-

ster of Agriculture or this Government that they should increase the price of cane. You have to increase the price because two factors have to be taken into account under the cane control order : what is the return from alternative crops and secondly, what is the actual cost of production ? Has the Ministry ever studied those two aspects ? Several times questions were put by us, even by MPs of the ruling party. In spite of all those questions, the Government had been displaying an utterly callous attitude towards the cane growers' demand for Rs. 100 per tonne. On the one hand they have been having illegal bilateral talks only with the millowners and are giving them concession after concession. But for the cane grower the price which was fixed in 1966 at Rs. 72.37 still continues, in spite of the fact that inputs such as fertilisers, etc. have been costing the farmer much more than before. What is the conclusion to be drawn from this ? Therefore, I demand from the Agriculture Minister that he make a statement here and now declaring Rs. 100 as the price of cane.

Now, as regards Orissa. Yesterday some statement was circulated by the Agriculture Ministry and in different zones the price that was given was left to the concerned people. Are you going to leave it to bilateral agreements with the sugar industry without a statutory minimum, which is an obligation, a mandatory obligation on this Government —to fix the cane price under the cane control order. This is an order under the Essential Commodities Act. Why should you bypass such a statutory provision and allow the growers to go to the doors of the millowners to beg for an increase in price ? Are you allowing the cane growers to organise themselves and gherao the millowners and take as much as they can ? You will not approve of that also. It is the duty of the Government to fix the cane price, the statutory minimum price. Here it is very loosely stated : 'It is imperative in the interest of cane growers, industry and consumers that the cane price should also be made higher'. Millowners will increase it. Have you no duty towards the growers who are two crores, in fact I agree with my friend who says it should be multiplied into five, that means ten crores or even fifteen crores of people who are concerned with this matter. The matter should be resolved by the Government today and the Government should declare that the price is Rs. 100 per tonne.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : I have been hearing the earlier speakers. I do not want to be emotional; I want to be practical. I do not know why the policy of the Ministry should be so violently attacked. I know how the policy has been pursued by Mr. Ahmed. When prices went up to Rs. 235 a bag of sugar, the other day he suggested to the co-operative sector and private sector sugar mills,—I am one of them— without putting any control, that sixty per cent of the sugar stocks should be delivered to the Government at Rs. 150 plus excise duty and the mills accepted it in full. The co-operative sector people immediately agreed for the proposal of the Minister and were supplying sugar at the above rate. So it cannot be sold for more than Rs. 2.10 per kg. in Delhi; if it is being sold at a higher price, it may be old sugar; when new sugar comes into the market it will certainly be sold at Rs. 2.10 a kg. The man who sells it at a higher price will certainly go to jail. This we must understand very clearly.

In 1969-70 we produced 43.6 lakh tonnes of sugar in 1970-71 it has gone down to

[SHRI M. GOPAL REDDY]

38 lakh tonnes. Now it is going to 33 lakh tonnes. In two years our sugar production has gone down by about 11 lakh tonnes. Meanwhile, in two years our sugar consumption has gone up by 12 lakh tonnes. We have to export about 3 lakh tonnes to Bangla Desh also. The minimum requirements of our country are not less than 50 lakh tonnes We are having only 9 lakh tonnes on hand. This year at any cost we have to produce 41 lakh tonnes. There is sugarcane, but there is danger of its being diverted to gur or khandsari and we may have a shortage of sugar So, I appeal to the Minister to persuade the sugar mill-owners and the co-operative sugar factories to pay a minimum of Rs. 10 per quintal to the sugarcane growers provided the recovery is 10 per cent. For greater recovery there should be proportionately higher price. In Maharashtra the sugar mills are already paying over Rs. 125 per bag because the recovery is about 12 per cent. In our State we are already paying Rs 88.20 where the recovery is more. I request the hon. Minister to call another meeting of the co-operative sugar factories and the representatives of the Sugar Mills Association to declare Rs. 10 per quintal for 10 per cent recovery with proportionate higher price for higher recovery.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY : Joint Stock companies should also be taken into consideration.

श्री रामचन्द्र विकल (बागपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान को इस देश में उस की लागत और मेहनत को देखते हुए केवल गन्ने का ही दाम नहीं मिलता, बल्कि उसकी जितनी भी पैदावार है, उस के परिश्रम और लागत के मुताबिक उसको दाम नहीं मिलता । यह दुर्भाग्य की बात रही है । इस देश में जहां किसानों को उचित दाम नहीं मिलता, वहां उपभोक्ताओं को उचित दाम पर चीजें नहीं मिलतीं । इसी असमंजस में सरकार आज तक तय नहीं कर पाई है कि किस तरह से हम पैदा करने वालों को उचित दाम दें और उचित मूल्य पर वितरण करा सकें । एक बड़ी जटिल समस्या हमारे देश के सामने खड़ी हुई है, सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

माननीय पाण्डेय जी ने जो सुझाव रखा है कि गन्ने का दाम कम से कम 10 रु० होना चाहिये और यह उचित दाम है, मैं भी इस का समर्थन करता हूं, उसे यह अवश्य मिलना चाहिये । लेकिन यहां किसान को 10 रु० गन्ने का दाम देने की बात चल रही है वहां मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसान को गन्ने का उचित दाम ही नहीं मिलता, बल्कि मेरठ जिले में कुछ ऐसी फैक्ट्रीयां भी है, जहां दो वर्ष से किसानों को गन्ने का दाम भी नहीं दिया गया है । मैं चाहता हूं कि सरकार उन को गन्ने का पिछला बकाया भी दिलाने की कोशिश करे । अगर यही हालत चलती रही तो जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है कि गन्ने की पैदावार कम हो जायगी, एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश के सामने आने वाला है । अगर किसान को गन्ने का दाम नहीं मिला तो मैं समझता हूं कि किसान गन्ने को पैदा करना ही बन्द कर देगा ।

यह बात सही है कि किसान की तरफ सरकार का ध्यान इस कारण नहीं है कि किसान का इस देश में अभी तक राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं बना है । जहां किसान में राजनीतिक दृष्टिकोण की कमी है, वहां सरकार भी उस की इस कमजोरी का फायदा उठाती रही है । मैं समझता हूं कि आन्दोलन करने, हड़ताल करने और दूसरी तरह के जो प्रदर्शन होते हैं, जिन से सरकार प्रभावित होती है, इस देश के किसान सभ्य रूप से उस बात को नहीं कर पा रहे हैं और उस कमजोरी का सरकार बराबर फायदा उठा रही है । आज किसान इस देश के लिये अन्न पैदा कर रहा है उस के बच्चे देश की रक्षा कर रहे हैं, पैदावार भी बढ़ाते हैं । अगर किसान को साधन और सम्मान नहीं दिया गया तो इस देश की गरीबी नहीं मिट सकती । गरीबी मिटानी है तो देश में पैदा करने वाले को साधन और सम्मान देना होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे कोई ठोस कदम उठायें । अब समय इस बात का नहीं रह गया है कि हम काग़जी जवाब देते रहें, हम को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण किसानों के बारे में अपनाना होगा । आज जितनी भी किसानों के बारे में विचार करनेवाली संस्थायें हैं उन में कभी भी किसानों का व्यावहारिक नुमाइन्दा नहीं रखा जाता । सरकारी अफ़सरों का दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं है और जो राजनीतिक नेता हैं वे भी किसानों की बातों को व्यावहारिक रूप से नहीं समझते हैं, इसी का नतीजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है । किसान अभी चुप है, लेकिन--

उठेंगे तो तूफ़ान बन कर उठेंगे,

अभी हम ने उठने की ठानी नहीं है

अगर देश के किसान खड़े हो गये तो फिर किसान की हर बात सरकार को माननी पड़ेगी इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि किसान की समस्या की तरफ़ ज़रूर ध्यान दें

*SHRI K. SURYANARAYA A (Eluru) : Mr Speaker, Sir, during the last five years, this House had discussed the issue of Government's Sugar Policy many times. Hon'ble Members from al parties had been pleading for a fair deal for the sugarcane growers. I regret to say, Sir, that this has become more or less a ritual with the Members highlighting the plight of the grower because of the minimum price fixed by Government and the Government repeating their intention to step in and do something to help the farmer. I am rather pained at this attitude of the Government. The Government is more solicitous about the needs and conveniences of the mill-owners but till today nothing much has been done for the sugarcane grower. After looking to the needs of the mill-owners, than probably they would, if at all, think of the needs of the grower. ow the Government has come out with the plea that in certain States the prices of sugarcane have been revised. But in the case of my own State, our Chief Minister has expressed his inability to do anything in the matter.

Because the Government does not have any clear-cut policy in regard to sugar, there prevails much confusion. The grower is not interested in producing sugarcane because there is no guarantee for him that he would get any remunerative price. If he starts cultivating tobacco, he is assured of its purchase by the various factories in the country. It earns a lot of foreign exchange and he is in a happy position because of this, with the fluid situation prevailing in regard to sugar, the farmer is increasingly shifting to the cultivation of other cash crops than sugarcane That is why you notice that over the last two or three years, the acreage under sugarcane cultivation has been dwindling and consequently the production of sugar has also come down to 22 lakh tonnes from about 45 lakh tonnes. But the Government does not seem to be awake to the serious situation developing now. They are more concerned with the amount of excise duty collected. I submit that this is not the correct way of looking at the problem.

Sir, in this House and outside, we have been demanding that justice should be done by the farmer and a remunerative price should be fixed for the sugarcane. You have seen here today, Sir, the unanimity of the demand from the spokesmen of the various parties that took part in this discussion. The demand has been for fixing the price at a minimum of Rs. 10 per quintal. Some of the Hon'ble Members have even asked for a higher price.

The Government consults all the Opposition Leaders for a consensus on any vital and crucial issue. We have seen this procedure in this session also. So,

*The original speech was delivered in Telgu.

[SHRI K. SURYANARAYNA]

in the case of sugar policy also, I request the Government to treat this as a national problem and invite all the leaders of the parties, and come to an agreed solution to this issue, of fixation of price for sugarcane.

I regret to say that the Government has been following a policy favourable to the mill-owners only. The All India Sugar Manufacturers Association and those who do not pay any excise duty have waited on the Government in a deputation and the Government have acceded to their request for decontrol. Earlier to decontrol, in certain parts of the country, sugar was available at Rs. 1.60 or so per kilogramme. But now sugar prices have shot upto more than Rs. 2.25 per kg. This is the effect of decontrol. To whom does this amount of rise in the retail price of sugar go ? Obviously not to the sugarcane grower. Over the last five years, as I have said earlier the members of this august House have been unanimously demanding a fair deal for the sugarcane grower and now the benefit goes to the mill-owners. It is a sad commentary on our professions and I am sorry to have to point this out here today.

The agriculturists are not an organized section of society. You are also aware that the wages of agricultural labour have also been going up. With the price he gets for the sugarcane, mostly in a distress sale, and with the additional burdens by way of wages for the agricultural labour and the general rise in the cost of living, one can easily imagine the miserable plight of the sugarcane grower. His plight cries for immediate redressal and justice. I, therefore, request the Government not to tarry and delay a decision on the fixation of a remunerative price for the sugarcane.

SHRIMATI SHEILA KAUL (Lucknow) : The year 1971 started with an opening stock of 14 lakhs tonnes of sugar. The estimated production for the current session would be 33 lakhs tonnes making a total of 47 lakhs tonnes. Out of this 40 lakhs tonnes would be for home consumption.

The hon. Minister had discussions with industrialists about sugar production and cane prices. It would have been much better if he had also consulted the sugarcane growers because they do the real job and they would have been able to tell us where the shoe pinches.

The Minister's statement says that it is the sugar industrialists who came forward to offer better prices to the cane grower. It would have been better if the government had taken the initiative of giving more price to the sugarcane growers than giving the initiative to the industrialists.

The prices fixed for sugarcane are less than what the growers wanted. While in UP we were given an assurance that it would be to the tune of Rs. 10, in Maharashtra it is Rs. 9. In Lucknow, the price of sugar has gone up. Not only in Lucknow, everywhere, the price of sugar has gone up. The Minister was kind enough to say that he would see that the prices do not rise. But the sugar price has risen every year.

There are about 2 crores of sugarcane growers and nearly Rs. 11 crores are due to them. No mention has been made in the statement as to how that money is to be given to sugarcane growers. Unless the farmer gets his return, he cannot put in good fertiliser and other things to get more yield from sugarcane. The sugar content cannot increase unless you put in good fertiliser and other things. So, I would urge upon the Government that the price of sugarcane should be at least Rs. 10 per quintal.

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : अध्यक्ष जी, इस सदन में गन्ने के दाम पर बहुत बार चर्चा हुई है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर दल के कहने के बावजूद, किसानों के एजिटेशंस के बावजूद हमारी सरकार ने कभी इस पर गौर नहीं किया। पिछली दफा जब शुगर प्राइस कन्ट्रोल हटाया गया तो पूरे देश को आश्वासन दिया गया था कि चीनी का दाम नहीं बढ़ेगा, मगर आज चीनी ढाई रुपये किलो बिक रही है और गन्ने का दाम वही पुराना चला आ रहा है जोकि दस साल पहले था सात रुपये 37 पैसे प्रति क्विन्टल। हमारे पूरब में एक कहावत है :

अन्धेर नगरी अंधा राजा,
टका सेर भाजी टका सेर खाजा...(**व्यवधान**)...

तो हमारे देश की सरकार की भी वही दशा है। सूखी लकड़ी 8 रुपये क्वींटल बिक रही है लेकिन गन्ने का दाम सात रुपये 37 पैसे क्वींटल है। इस अंधेर का कोई ठिकाना नहीं है। यह सारा काम इसलिए हो रहा है कि हमारे देश के जो शुगर मैगनेट्स हैं वह सरकार को चन्दा देते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि गन्ने का दाम न बढ़े। पिछली दफा कई माननीय सदस्यों ने सदन में कहा कि करोड़ों और अरबों रुपया मिल मालिकों को सरकार ने दिया जिससे उन्होंने काफी मुनाफा कमाया है लेकिन वे काश्तकारों को उनका दाम नहीं देना चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों का सात करोड़ रुपया मिल मालिकों पर बकाया है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिस किसान ने अपना गन्ना सौ रुपये का बेचा है वह अपनी पर्ची 25 रुपये में बंधक रख कर अपना काम चला रहा है क्योंकि उसको पैसा मिलता ही नहीं है। वे सोचते हैं कि सौ रुपए का जो गन्ना बेचा है अगर उसका पेमेन्ट नहीं होता है तो 25 रुपये में ही उसको बंधक रख कर अपना काम चलाओ। लेकिन लगातार दबाव डालने के बावजूद सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी हमारे भाई सिकल जी बोल रहे थे, वे गन्ने के क्षेत्र से आते हैं, हम तमाम लोग भी ऐसे क्षेत्रों से आते हैं और हम यह महसूस करते हैं कि आज गन्ना पैदा करने में लागत ज्यादा आती है, पानी का दाम ज्यादा लगता है और दूसरी चीजें मंहगी हैं। हमारे यहां एक और अंधेर है। घनश्याम दास बिड़ला को हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार लागत से कम पर बिजली दे रही है रिहन्द डैम की। यानी जितनी बिजली पैदा करने में खर्चा होता है उससे भी कम पैसे पर बिड़ला को हिंडैलियम में बिजली दी जा रही है, लेकिन किसानों को बिजली मंहगी दी जा रही है। किसान के लिए आज गन्ने की लागत बढ़ गई है क्योंकि खाद के दाम बढ़ गए हैं, लेबर चार्जेज बढ़ गए हैं और पानी के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन गन्ने का दाम वही चला आ रहा है।

तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश में इमर्जेन्सी है। हम सभी तैयार थे कि गन्ने के काश्तकारों का आन्दोलन हो क्योंकि उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन चूंकि देश पर संकट आ गया, इसलिए सबने मिलकर उसको फेस किया है और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार अब इस मामले में ज्यादा डिले न करे, कम से कम दस रुपए क्विंटल गन्ने का दाम किसानों को दिया जाये 9 परसेन्ट की रिकवरी पर और वह अगर इससे ज्यादा होती है तो ज्यादा दिया जावे वरना हमारे काश्तकार उजड़ जायेंगे और गन्ने की खेती वह नहीं करेंगे। इस सदन में न तो मैं कोई धमकी देना चाहता हूं और न कोई झगड़ा करना चाहता हूं।

लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि 'आ बैल, मुझे मार' वाली पालिसी आपको छोड़ देनी चाहिये। आपको देश के काश्तकार का आदर करना चाहिये। अगर देश का काश्तकार सुखी रहेगा तो आपके दूसरे जो धंधे हैं वे भी चल पाएंगे और अगर काश्तकार को नुकसान होगा तो देश में अमन कायम नहीं रह सकेगा और देश का आर्थिक ढांचा भी छिन्न-भिन्न हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप आज ही ऐलान करें इस बात का कि कम से कम दस रुपये क्विंटल गन्ने का दाम होगा। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, आप किसी से पूछ लें और वह आपको बता देगा कि चीनी मंहगी होती जा रही है। किन्हीं क्षेत्रों में तो चीनी मिलती भी नहीं है। मेरा आप से अनुरोध है कि केन का दाम आज ही बढ़ा कर आप तय कर दें।

MR SPEAKER The hon Minister

SOME HON MEMBERS *rose*

MR SPEAKER The rule is that the members who had not sent their advance intimation cannot be allowed I have accommodated all those who have sent me their names

The hon Minister

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI F A AHMED) Mr Speaker Sir I am grateful to the hon Members who have made their observations on a very vital policy So far as sugar policy is concerned in the course of the discussion a large number of questions have been raised One particular question on which emphasis has been laid by hon Members is regarding the price given to the sugarcane grower

I would like to deal with the important points which have been raised in the course of this discussion and I would like to point out that after taking into consideration the general economic picture, the observations made by the growers, the observations made by the industry and by the Agricultural Price Commission, the Government fixed the minimum price of sugarcane at Rs 7 37 for recovery of 9 4% Here, in fixing the price, I just want to bring to the notice of the House that this was a notional price. Below this price they should not sell the sugarcane but there was nothing to prevent the sugarcane growers to get a higher price than the minimum price that has been fixed by the Government (*Interruptions*) Now, therefore, because we did not increase the minimum price for other foodgrains, it was, therefore, considered necessary that the minimum price fixed last year for sugarcane also should not be increased having regard to the economic conditions and the effect any increase in sugarcane price will have on other foodgrains Anyhow, the hon Members are aware that the price of sugar was increasing from time to time and we had sufficient sugar Therefore, we allowed decontrol in order that the forces of demand and supply may have free play and a reasonable price for sugar arrived at But when we found that the price of sugar was increasing and the sugarcane growers were also not getting the higher price than the fixed by the Government I sent for all the industrialists and the co-operative owners and had a discussion with them and after discussion it was agreed that the minimum price given by them except in a few States will be Rs 8 50 and in some places like the Western U P it will be Rs 9 In Maharashtra it will be about Rs 11 In Punjab also it will be

SHRI M RAM GOPAL REDDY In Maharashtra, it is for field delivery

SHRI F A AHMED In the Punjab it will be Rs 9 per quintal It is true that so far as Andhra Pradesh Tamil Nadu, Mysore and one or two other areas like Orissa are concerned, no agreement has yet been arrived at But it is our effort that there also the minimum price paid to the sugarcane growers should not be less than Rs 8 50 That has been accepted by them and that is the advice given by us and accepted both by the industry as also by the co-operatives and I hope that the cane-growers will now get more price than what has been statutorily fixed by the Government

AN HON MEMBER What about Bihar ?

SHRI F A. AHMED In Bihar, the minimum price is Rs 8 50

श्री विभूति मिश्र : वैस्टर्न यू० पी० में रिकवरी कम है और गन्ने का दाम आप नौ रुपये दिलवा रहे हैं। हमारे यहां रिकवरी अधिक है लेकिन साढ़े आठ रुपये ही आप दिलवा रहे हैं, ऐसा क्यों ?

SHRI F A AHMED In UP it is Rs 9 (*Interruption*) If there are any complaints that this price is not being paid if such complaints are brought to my notice, I will certainly look into it

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY The representation of the sugar-mill owners association itself was given in the month of September What has happened to it ? They said that they will pay Rs 9 at least as minimum cane price Why have you not accepted that ? Why have you fixed Rs 8 50 or agreed with the millowners ?

SHRI F A AHMED We have not fixed That was our recommendation that minimum should be like that If he is prepared to pay higher price we have no objection to that We have not fixed any rate at all

Hon Members are aware that the price of sugar early in December has been increasing to nearly Rs 2 3 or Rs 2 25 per k g It has been agreed to by the mill-owners that consumers will get 60% of the sugar at Rs 2 per k g through the fair price shop Now, 40% will be the free sugar for which the price as it is now prevailing would be Rs 2 3 per k g My information is that the present price is Rs 2 3 or Rs 2 25 It is not more than Rs 2 35 in any place But, I hope this will provide a tremendous relief so far as the domestic consumers are concerned, because according to our assessment only 30% of the sugar released is required for the purposes of domestic use and we have increased this to about 60 per cent Therefore all the domestic consumers will get sugar at fixed price except in Delhi where due to octroi duties, the price will be more by 8 or 9 paise compared to other places

PROF S L SAKSENA : Have you fixed the price of free sugar ?

SHRI F A AHMED We have not fixed the price of free sugar

AN HON MEMBER It will sell at Rs 5

SHRI F A AHMED It cannot be Rs 5 Actually if anybody wants more he can buy in the free market and he will pay higher price than what is fixed

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY How much higher ? Why do you not propose nationalisation of these factories ? What is now in between ?

SHRI F A AHMED If they charge unreasonable price Government will certainly take necessary action It will not be more than Rs 2 35 or Rs 2 3 which is now prevailing before this agreement was arrived at

Then the question was asked about the sugar policy We have certain objectives which we wish to pursue and which we are pursuing One of the objectives is that we must have sufficient production in the country which will satisfy the consumers demand in the country It should not only fulfil the consumers demand, but will have to cater to export also under our commitment to outside countries One of the objectives is that consumer should get sugar at reasonable prices The third objective is that the cane-growers should get reasonable price for cane cultivation These are the objectives which we have been pursuing and having regard to the general economic condition we thought that this was not the opportune time when the statutory minimum price fixed by us should be increased to more than what was fixed last year, and, therefore, we have maintained the *status quo* But, as I have pointed out, that does not mean that the sugarcane growers will have to sell their sugarcane at those prices They

[SHRI F.A. AHMED]

can get prices higher than that fixed by Government. I am glad to announce, and I think the House is already aware of it, that in nearly 83 per cent of the areas, the industrialists and co-operatives have agreed to give a higher price than that fixed statutorily by Government, and the minimum which they propose to give in these areas is Rs. 8.50, but in many places they will be getting even higher than that, and if there is any complaint from any quarter, I shall again look into this question and see that the minimum agreed to by them is actually given to the cane-growers.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Are Government going to change their policy for the whole year ?

SHRI F. A. AHMED : We do not wish to change the policy, but if circumstances demand and if the industrialists do not behave properly, then Government will have to consider changing the policy in order to see that the consumer gets sugar at a reasonable price and the cane-growers also get a reasonable price for their cane. Another question which had been raised was that the production of sugar was going down. It is a fact that sugar production has gone down during the last two years. But there are several reasons for this. One of the reasons, why during this year particularly sugar production has gone down, is that not only was there less are a under sugarcane cultivation but there have also been bad crops in a large number of areas. In Maharashtra, on account of scarcity of rains, the crop has suffered. In Bihar and UP, sugarcane cultivation has suffered because of floods. So, there is less sugarcane than last year, not only because the area under cultivation is less but also because of bad weather conditions. It is also true that in UP and Bihar and particularly in UP, the area under cultivation is less. The reason for this is that the cultivators there think that it is now more profitable for them to have cultivation of other crops in the land than sugarcane cultivation. Sugarcane takes practically the whole year while if the land is utilised for purposes of cultivation of other things, they can have multiple crops and so on and they can yield better results or better income because of better utilisation of land. Therefore, there is some diversion from sugarcane cultivation to cultivation of other crops.

SHRI B. P. MAURYA (Hapur) : If Government do not increase the price now, the area will go down still further.

SHRI F. A. AHMED : That is not the reason. We do not wish to compete, as I have already pointed out. It is also necessary for us to have other foodgrains which will be very helpful for the country's economic condition, and, therefore, we do not want to have competition between one crop and another. We shall see that we try to have whatever sugarcane is required for purposes of increased sugar production, and we should also give reasonable price to the sugarcane growers.

I hope with this minimum price now agreed upon by the industrialists and co-operative factories, it will be possible for the sugarcane growers to get higher prices than what has been fixed by Government, namely, Rs. 7.37 linked with 9.4 per cent recovery. If the recovery is more than 9.4 per cent, the sugarcane grower will get a higher price. One hon. Member has pointed out that for a recovery of 10 per cent, the price should be fixed at about Rs. 10. That will be the amount more or less which they would get. Where the recovery is better than 9.4 per cent, the sugarcane price will be higher than even Rs. 8.50 or Rs. 9 fixed for these various sectors

I thank hon. Members for the interest that they have taken.

I can assure the House that when these questions arise, we shall keep in view this matter as to how we can serve the interests of the cane-growers and consumers. We shall always be watchful about their interests and shall do whatever is necessary.

SHRI K. NARAYANA RAO : What about molasses and rectified spirit ?

श्री विश्वनि मिश्र : क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि कीमत तय करने के समय लोक सभा के सदस्यों को भी बुलाया जाये जैसे कि मिल-मालिकों को बुलाया जाता है, ताकि उन की बात सुनने के बाद कोई फैसला किया जाये ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : लोक सभा के मेम्बर हमेशा अपनी ओपीनियन देते हैं । उन की ओपीनियन हम लेते हैं और लेते रहेंगे ।

11.56 Hrs.

ADDRESS BY THE SPEAKER

MR. SPEAKER : Before I go on to the next item, I have to make a few observations.

We are going to adjourn *sine die* today. There are a number of motions which were very important and which ought to have been brought during this session for discussion as members were very keen that they should be discussed. But we could not take them up as because of the emergency a number of other Bills and Motions came up. So when we commence the next session, all these pending motions which still carry their value at that time will be brought up. Members may please rest assured about that; we will try and accommodate them.

AN HON. MEMBER : What about questions ?

MR. SPEAKER : The rules will apply.

SHRI B. P. MAURYA (Hapur) : Will the next session be a budget session or a short session ?

MR SPEAKER : What does he like?

SHRI B. P. MAURYA : If UP is going to the polls, a short session.

MR. SPEAKER : The second thing is this. I have a right to advise the young members. In this particular case, I am referring to Shri N. N. Pandey. He was quite angry and in his anger threw away some books. Perhaps nothing could prevent him from doing that. But we are quite a mature House. We should avoid such outbursts. These do not add to the logic of the case or argument. You have a very fresh example. The Pakistan representative in the Security Council, who now happens to be the President of that country, just rushed out after tearing the Charter and throwing it away. But still that did not add to the logic of his argument.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Gorakhpur) : I am sorry this happened. I did not mean it.

SHRI B. P. MAURYA : It was because of that that he has become President.

MR. SPEAKER : I hope my hon. friend is not infected by him. We do not want to show that immaturity in our legislature which was displayed by him there. We all condemn it and we should not allow it to happen in our House.

Thirdly, before I leave the Chair—the Deputy-Speaker will be taking over now —I wish to avail of this opportunity to thank all the members of the House for the great sense of patriotism and unity shown in this hour of emergency. I can safely say that during all these years that I remember, Parliament did not show